Now I am calling Shri Ram Vilas Paswan on the Calling Attention.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: Do not record anything.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Ram Vilas Paswan.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED IMMIGTATION VISA RACKET UNEARTHED IN DELHI

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय गृहमंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"दिल्ली में अप्रवास वीसा की जाल-साजी का पता चलने के समाचार और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH):

Mr. Deputy-Speaker, Sir, a few cases have come to notice in Delhi where certain unscrupulous elements have cheated job seekers wanting to emigrate to foreign countries, by resorting to forgery of travel documents including passports and visas. During the year 1982, the Delhi Police have registered 7 cases against visa racketeers operating in groups. Besides, 36 other individual cases of similar nature have also been registered so far during the year. In this connection, 50 persons were arrested.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): What are their names? Give their names so that the people know about them.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Mr. Agrawal you had been a Minister sitting here. I am doing what you were doing previously. If supplementaries are put and if I am required to give an answer, I will give.

SHRI SATISH AGARWAL: I would not be allowed to put supplementaries and ask for information. That is why I am interrupting.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: After I make the statement, you can interrupt.

Sir, 37 of the cases are under investigation and challans have been filed in court in 3 cases which are pending trial. 3 cases have been filed as untraced.

In the latest case reported to the Police on the 10th October, 1982, 3 Travel Agents of Delhi were arrested. Their arrest has led to the recovery of a number of passports and other forged documents. According to Delhi Police, the arrested persons have cheated a large number of persons. Investigation of the case is in progress.

Indian passport-holders, desiring to proceed to foreign countries for visits, employment etc., are required to submit aplications to the diplomatic mission in India of the foreign country concerned for obtaining visa on their passport. The procedure for granting visas and the time taken in the matter may vary from mission to mission.

Police take immediate action to proceed against the culprits in accordance with the relevant provisions of law, on receipt of complaints of forgery and cheating in regard to issue of visas and job racketeering. Besides, the intelligence net-work of the Delhi Police has also been strengthened to collect information about such activities.

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय सदन आज फिर जाली वीसा के बारे में विचार कर रहा है। इसी संबंध में मैंने कालिंग एटेंशन दिया है यह एक ऐसा विषय है, जिस पर समय-

[श्री राम विलास पासवान]

समय पर जाली वीसा के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। विभिन्न समाचार पत्रों ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मुझे दुःख हुआ क्योंकि सरकार ने फिर वही घिसा-पिटा जवाब, बना-बनाया जवाब दे दिया है। लेकिन सरकार ने यह नहीं बतलाने का काम किया है कि यह जालसाजी का कारण क्या होता है। जाली-वीसा कहां से उत्पन्न होता है और दूसरी बात इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बेसिक बात यह है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चहिये। यह सिर्फ आपके ही मंत्रालय का काम नहीं है। इसमें सिर्फ होम मिनिस्ट्री ही जिम्मेदार नहीं है, लेबर मिनिस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। इसलिये मैं चाहता था कि दोनों मिनिस्टरों की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए था तो निश्चित तरीके से कुछ सुधार हो सकता था। लेकिन सरकार ने अपना जवाब दे दिया कि 50 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और 37 मामलों की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस को जैसे ही वीसा के संबंध में जालसाजी और धोखाधड़ी तथा नौकरी के बारे में घोटाला करने की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो वह अपराधियों के विरुद्ध कानून के संबंधित उपबंधों के अनुसार तुरन्त कार्यवाही करती है।

यह शिकायत आपको किस के द्वारा मिलती है। जब आप को आम आदमी शिकायत करेगा, तब आपकी नजर खुलेगी लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है गुप्तचर विभाग है या दूसरा विभाग है उनसे कभी आपको शिकायत मिली है। जब कभी आपको शिकायत मिलती है तभी आपकी नजर जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जालसाजी का जन्म कहां से होता है। आज हिन्दुस्तान में बेरोजगारी की समस्या है जहां कहीं लोगों को मालूम होता है कि रोजगार मिलने वाला है, तो लोग रोजगार पाने के लिये गांव से दौड़कर दिल्ली आते हैं, बम्बई आते हैं। जब हताश हो जाते हैं कि यहां भी काम नहीं मिलेगा, तो वे बाहर विदेशों में जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि विदेशों में जाकर काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। इस प्रकार वे घर बार छोड़कर जेवर-गहना बेचकर आता है, लेकिन सरकार के पास कोई एजेंसी नहीं है।

जब माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे तो उनसे जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो प्राईवेट एजेंसीज को अलाउ किया है ये कौन-कौन सी हैं। मैं कहना चाहता हूं सारा का सारा दोष इनजाम में है। इनजाम में दोष की वजह से यहां सब होता है। आप देखिए नाईजीरिया के दूतावास में वीसा विभाग बन्द पड़ा है। वहां बेरोजगार लोग चक्कर लगाते हैं तो वहां उनको दलाल मिलते हैं। वे उनसे पैसा लेकर उनको जाली पास-पोर्ट जाली वीसा और जाली फर्म का नाम देते हैं और कहते हैं कि वहां चले जाओ तुमको नौकरी मिल जायेगी। लेकिन जब वह आदमी वहां जाता है तो वैसी कोई फर्म नहीं होती। इसके बाद कहीं पुलिस के चक्कर में आ जाता है तो पुलिस उसको बन्द कर देती है। इस तरह के समाचार भी आए हैं कि इण्डियन एंबेसी के द्वारा ऐसे लोगों को छुड़वाकर

स्वदेश भेजा गया है । इस तरह के कारोबार चल रहे हैं । इसी तरह से पाकिस्तान एंबेसी है वहां चले जाइए तो वहां भीड़ लगी रहती है । सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है एक तरफ तो सरकार यहां पर लोगों को रोजगार नहीं दे पाती और भुखमरी की स्थिति है, नौजवान पढ़-लिख कर मारे-मारे फिर रहे हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है और जब विदेश के बारे में वह सोचता है तो आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है । क्या सरकार कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती है सरकारी अफसरों और प्राइवेट एजेंसियों की सांठगांठ से ये सारे काम चलते हैं । सरकार अपनी जवाबदेही से हट नहीं सकती और जिन लोगों को सरकार ने लाइसेंस दिए हैं वे भी किसी न किसी रूप में इस धंधे को प्रोत्साहित कर रहे हैं ।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, कोई इस तरह का कारपोरेशन तैयार किया जाए और प्राइवेट एजेंसियों से इस काम को लेकर अपनी एजेंसी के माध्यम से रोजगार के इच्छुक लोगों को विदेश भेजने का काम किया जाए ?

मैं बताना चाहता हूं , यह "ब्लिट्ज" है इसमें नाम देकर के सारा विवरण छापा गया है "करोड़ों रुपये का वीसा घोटाला" 15 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक लिये गये हैं । लेकिन सरकार तो अखबारों को गाली देगी, अखबारों को बदनाम करने की कोशिश करेगी, अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का काम होता है, जरनलिस्टों को पीटने का काम होता है, लेकिन अन्त में समाचार भी अखबार का ही सही निकलता है । जब अखबार में निकलता है तब सरकार का ध्यान जाता है और सरकार कहती है कि यह समाचार सही है ।

मैंने इसके बारे में एक बार राज्यसभा में भी प्रश्न उठाया था, तब भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया था और अब फिर घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है । जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाये जायेंगे, तब तक यह पुनरावृत्ति होती रहेगी ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है । अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है , उनमें से कितने लोगों पर कार्यवाही की गई है, कितने लोगों को कौन कौन सी सजायें दी गई हैं । जो वर्तमान कानून हैं क्या उसमें कहीं संशोधन की आवश्यकता है । अगर है तो उस के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो वीसा के बंगलिंग्स हुये हैं रैकेट पाये गये हैं, क्या उनमें सरकारी अधिकारियों का भी हाथ रहा है । अगर है तो कितने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है । कितने रैकेटियर्स को पकड़ कर जेल में बन्द करने का काम किया गया है । और आगे के लिये सरकार के पास क्या योजना है, जिसके तहत सरकार लोगों को विदेश भेजने की व्यवस्था करे और जालसाजी करने वालों को मौका न मिले ।

क्या सरकार अपनी एजेंसी को इतना चुस्त और स्वस्थ कर देगी, जिसके माध्यम से जो लोग विदेश में जाना चाहें, वह चले जायें, और वहां जाकर फंसे नहीं, उनको रोजगार भी मिले । हमारे यहां से कुछ लोगों को ले जाया गया कि तुमको तीन हजार रुपये मिलेंगे, लेकिन उनका जो पासपोर्ट होता है, वह जेल में रखा रहता है । जहां एक तरफ जाली वीसा और जाली

[श्री राम विलास पासवान]

कारोबार होता है, वहां दूसरी तरफ, जो सही काम से जाते हैं उनको पैसा नहीं मिल पाता है ।

मैं, दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं । पहला, क्या केन्द्रीय सरकार अपना कारपोरेशन बनाने के लिये विचार करती है जिसके माध्यम से लोगों को विदेश में भेजने का काम हो सके । दूसरा, अभी तक आप ने किन किन और कितने लोगों को एजेंसी दी है और लोगों को विदेश में भेजने की उनकी कैपेसिटी क्या है ? तीसरा, आपने अभी तक कितने लोगों तथा अफसरों के विरोध में कार्यवाही की है जो जाली बीमा का काम करते हैं ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: The Hon. Member has put some comprehensive questions and he has brought forward the entire gamut of...

MR. DEPUTY SPEAKER: In the end, he has put some pointed questions.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: No, no. He has raised some very relevant points. I would like to answer one by one, if he has got some patience to listen to me.

There was one Immigration Act, 1922. That was drafted keeping in view the problems of indentured labour during British regime. That Act was being followed with regard to giving visa for the people who go for jobs abroad.

But in 1979, the Supreme Court has said that:

> "That particular Act is outdated and is not suited to the conditions of labour abroad."

They said:

> "Prior to that, the recruiting Agencies were required to be registered with the Government and such agents numbered 802"

at that time, that is, in 1979.

The Supreme Court declared the system of registration void inasmuch as the system was purely administrative, without any statutory support. As a result, the field of recruitment was thrown open and any individual could undertake the recruitment of workers for employment abroad without any screening of prior approval. This particular field of enterprise, being highly remunerative, removal of registration requirement gave rise to uninhabited growth in the number of recruiting agents who could either be regularly constituted firms or private individual working for quick profits. It has not been possible, therefore, for the Government to keep track of the individuals working for quick profits who have been recruiting manpower for export.

This is our difficulty.

Afterwards, the Supreme Court has laid down certain guidelines with regard to the recruitment of labour.

According to the guidelines stipulated by the Supreme Court, presently the channelising of recruitment is being done according to the Supreme Court Order under which the foreign employers can recruit workers either directly through their own representatives or through any Indian agency authorised by them to recruit on their behalf. For this purpose, the recruiting agencies are required to complete the immigration formalities in accordance with the guidelines laid down by the Supreme Court which, *inter alia*, provide for registration of employment contract, furnishing of security deposit etc. with the Protector of Immigrants. In the absence of an Act, whatever guidelines have been laid down by the Supreme Court are being followed by the Government.

Now the Labour Ministry has correctly said—first it was with the Ministry of External Affairs and it is transferred to the Ministry of Labour—that it is formulating a comprehensive Bill to regulate these people going abroad. A Committee of Ministers was also constituted to make a comprehensive Bill. The main intention of this is that, when the Bill is drafted and placed before Parliament for being enacted, certain important items should be borne in mind or taken into consideration.

These are some of the constraints which have been taken into consideration by the Ministers while formulating this Bill.

Such of those Ministries, as particularly those involved in projects abroad, are having an interest in the proposal; also the proposals contained in the Bill have a bearing on our capacity to utilise effectively the labour market abroad; also to take into consideration the deteriorating balance of payments position; also it should not resut in obstructing Indian workers from going abroad or in reducing the competitiveness of Indians executing projects abroad.

These are the guidelines or the guiding factors which are before the Ministry to prepare a comprehensive Bill to regulate these matters, so that unscrupulous elements may not take advantage of the situation. I agree with the hon. Member. There is unemployment in this country and the manpower utilisation is, to some extent, limited so far as our country is concerned. And there are other countries where our manpower can very profitably be utilised. We in the Government of India are trying to regulate these people being sent abroad in a rational manner keeping in view the factors I have enumerated now and also to see what action could be taken against such of those persons as indulge in these activities. This is what they have mentioned in the Bill. I have also given the number of cases that were booked and the action that is being taken.

For the benefit of the hon. Member I may say that, at one time, it was also proposed to set up one Overseas Manpower Corporation also. However, the proposal was not pursued because continued growth of overseas emigration was not certain and the objective was to protect the workers. Not only that, several State Governments have constituted their own Manpower Corporations. For instance, Sir, your own State of Tamil Nadu also has done it. We do not want to duplicate or create difficulties for those Corporations. That is why, the Government of India is seriously thinking whether we can set up a sort of coordinating cell to see that these Manpower Corporations that have been set up in various States could be regulated, whether there should be a sort of coordination from the Government of India in the Ministry of Labour. These are the important steps that are being taken in this regard.

The hon. Member has also raise a point about emigration, that there is some *golmaal* in the Emigration Department. I may tell you, we have set up a procedure for obtaining emigration clearance for deployment of workers on behalf of foreign employers.

In accordance with the orders of the Supreme Court of India dated the 20th March, 1979, any individual, firm or organization can recruit and deploy workers on behalf of his or their foreign principals provided he has in his possession the following documents: (i) the power of attorney executed by the foreign principal authorising them to recruit workers on his behalf duly authenticated by the Indian Embassy in the country of deployment; (ii) letters of demand indicating the category and number of workers required to be deployed, along with the wages payable duly authenticated by the Indian Embassy. (iii) Employment agreement proposed to be executed between the employer and the employee."

On the basis of the above documents, the protector of emigrants, whose offices are located at Bombay, Calcutta, Madras, Delhi, Cochin, Trivandrum and Chandigarh, after thorough scrutiny of the documents, grants emigration clearance.

The recruiting agent is therefore required to submit a bank guarantee bond on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/-. The amount of bank guarantee is as per scales given below. I shall give the particulars, if the hon. Member wants it. After the bank guarantee has been submitted, the Protector Emigrants grants emigartion clearance finally and make suitable endorsements on the passports of the workers and also on the employment agreement, a copy of which is registered with this Officer.

In certain cases where the emigration clearance is not required, necessary endosement suspending the emigration clearance is also granted. These are some of the

[Shri P. Venkatasubbaiah]

steps that are being taken. He has also said that some government employee is involved in this racket. So far, we do not have any information. If the hon. Member brings forward any specific instance, I assure him that deterrent action will be taken against such of the Government employees as are involved in this racket.

श्री राम विलास पासवान : आपने कितने लोगों को प्राइवेट लाइसेंस दिया है और कितने लोगों को कैपेसिटी के लिए

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: That system is not there. I said that we follow the guidelines laid down by the Supreme Court. That system has been given a go-by because of the order of the Supreme Court. That is why the Supreme Court have laid down certain guidelines and we are following those guidelines.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Paswan, the Emigration Bill is coming up later on. Now, Prof. Mehta.

प्रो० अजित कुमार मेहता : (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने कहीं तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है अपने बचाव के लिये...

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : हमारे सब के बचाव के लिये / सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पढ़ लेने दीजिये जो आपने स्वयं उद्धत किया है दूसरे सदन में इसी विषय पर चर्चा के सम्बन्ध में :

'The Supreme Court has further been assuring the Counsel. The Court orders as follows:

"We stay the operation of order dated 20th March 1979 read with order dated 30th July, 1979 until the Parliament passes a legislation on the subject."

यह 1979 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। मतलब यह है कि 1979 में ही यह समस्या खड़ी हो गई थी और सरकार को मालूम था। 3 साल इस बिल को लाने में लगे, लेकिन अभी तक कामप्रीहेंसिव बिल तैयार नहीं हो सका। लगता है कि अचार की तरह से है कि जितने ज्यादा दिन लगाये जायें उतना ही अच्छा होगा। पता नहीं कब सामने आयेगा वह बिल। तो 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक डैड लाइन दी थी...

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Guideline, not deadline.

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में एक डैड लाइन दे दिया था कि इस समय तक, 30 जुलाई 1979 तक आ जाना चाहिये इसके बारे में लेकिन उसको उन्होंने बाद में अमेंड किया जो कि मैं ने पढ़ा है। 'Until the Parliament passes a legislation on the subject'.

तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि टेक्नीकैलिटी का सहारा ले कर हम इस बिल को पेंडिंग रखें। पता नहीं कब तक? ईटर्निटी तक?

तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन हमारे ख्याल में आपने टेक्नीकैलिटी का सहारा लिया है... (व्यवधान)

AN HON. MEMBER: Doomsday.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He said that Government has taken action He said that 820 people have been arrested.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Let me complete my submission.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He said that Government is also taking action.

प्रो० अजित कुमार मेहता : आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइड

लाइन्स दिया है, और इतने दिनों तक जो कमियां हैं वह सामने आयी हैं..... उस पर आप क्या विचार करेंगे ?

एक तो यह कि एम्पलायरको डायरेक्टली यहां पर रिक्रूट करना चाहिये, तो यह ठीक है । आपको पता है, हिन्दुस्तान में बहुत से अखबारों में ऐसे झूठे विज्ञापन प्रकाशित कर दिये जाते हैं, नाइजेरिया और सऊदी अरेबिया की ओर से या और और दूसरे दूसरे स्थानों की ओर से, जहां कि मजदूरों के जाने की संभावना होती है। कि इतने इतने मजदूरों की जरूरत है। और वह वही रैकेटीयर्स करवाते हैं । जब प्रकाशित हो जाता है तो उनके आधार परयर ये लोगों को बरगलाकर भरती करना शुरू कर देते हैं।

दूसरी गाइड लाइन है जितने भी मजदूर भेजे जायें, प्रत्येक मजदूर के हिसाब से कुछ जमानत की रकम जमा करवा ली जाये । उसमें ये क्या करते हैं, रैकेटियर्स ? जितना रुपया जमा कराना है जमानत के रूप में, उतना रुपया वह पहले ही मजदूर से वसूल कर के रख लेते हैं,तब आगे की बात करते हैं कि भेजा जायेगा या नहीं भेजा जायेगा । कभी कभी तो ऐसा होता है कि रुपया जमा करा लेण के बाद भी उन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, वह घूमते रहते हैं ।

इस संबंध में 'दिनमान' का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जयप्रकाश कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने बहुत पहले ही ऐसी धोखाधड़ी की थी और जब मजदूरों ने मांग की कि उनको विदेश भेजा जाना चाहिये ,

(व्यवधान)

"दिनमान" के 27 जून—3 जुलाई, 1982 के अंक में जो लिखी है, उससे पहले 27 मार्च, 82 के अंक में भी खबर प्रकाशित हुई थी । जिसमें कहा गया था कि जयप्रकाश कम्पनी के माध्यम से कुछ हजार मजदूरों की बहाली विदेश जाने में लिये हुई और उसके बाद उनको विदेश के न भेजकर वसन्त विहार के पांच सितारा होटल "सिद्धार्थ इंटर कांटीनेन्टल" के निर्माण कार्य में लगा दिया गया और उनको उचित मजदूरी भी नहीं दी गई। इस पर उन मजदूरों ने संघर्ष किया और इस कम्पनी को सार्वजनिक रूप से मजदूरों से माफी मांगनी पड़ी और मजबूर होकर उन मजदूरों को बगदाद भेजना पड़ा। वहां जाकर उनके ऊपर क्या जुल्म हुये, वह जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं—

"मगर बगदाद में इन मजदूरों के लिये ज्यादा यातनापूर्ण नरक इंतजार कर रहा था जो उन की कल्पना से बिल्कुल विपरीत था । निर्माण मजदूर एकता समिति, दिल्ली के संयोजक को उड़िया में लिखें एक सामूहिक पत्र में, जिस के साथ डेढ़ सौ मजदूरों के हस्ताक्षर हैं, भारतीय मजदूरों ने वहां से किसी भी तरह मुक्त कराये जाने की मार्मिक अपील की है",

और उनको बाहर पत्र भेजने की भी इजाजत नहीं थी । किसी तरह यह पत्र उन्होंने भेजा जो यहां मिला, उससे मामला प्रकाश में आया । आगे इस पत्रिका में क्या लिखा है—

"ईराक में इन जमजदूरों को सुबह चार बजे जगाकर एक रोटी और एक कप चाय देकर बसों में बिठा दिया जाता है, पच्चीस तीस किलोमीटर की दूरी तक ये बसें मजदूरों को लेकर जाती हैं, जहां वे दोपहर एक बजे तक काम करते हैं । एक बजे उन्हें

प्रो अजित कुमार मेहता]

खाने के लिये ले जाया जाता है। यह खाना "कुत्तों के खाने लायक भी नहीं होता" और भूखे मजदूरों के सामने बहुत थोड़ी मात्रा में फेंक दिया जाता है। खाने के बाद दुबारा काम शुरू होता है जो अममन ग्यारह बजे रात तक चलता है सारे समय जोर जबर्दस्ती, गालीगलौज और धमकाने का सिलसिला लगातार चलता रहता है। आधी रात को काम से लौटने पर पता चलता है कि पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं। पेय जल का अभाव उनकी जिन्दगी की एक सामान्य स्थिति बन जाता है। रात को खाने के नाम पर मुट्ठी दो मुट्ठी सूखा भात उनके सामने डाल दिया जाता है। सब्जी का होना न होना प्रबंधकों की की खुशी पर निर्भर करता है।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: In Calling Attention, you are quoting all this.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Sir, otherwise I will not be able to make my point clear.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But the point is that you cannot take so much time. There are other items in the List of Business for the day. We have to take them up. Next I have to take up Matters under 377.

प्रो० अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमेशा हमारे सामने लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, थाड़ा रिलैक्स तो कीजिये।

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Don't draw your line.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Professor, I may allow also, but the point is that we have got to take up Private Members business at 3.30 p.m. Before that there are Matters under 377 and so many items. Only in the interest of all the Members, I am requesting you.

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप हमारे सामने हमेशा लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। इससे क्रम टूट जाता है...

(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Therefore, I am requesting you. Otherwise matters under 377 will not be taken up before 3.30 p.m. So, please cooperate.

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं कहना चाहता हूं कि अंततोगत्वा जब ये मजदूर वहां के भारतीय दूतावास में पहुंचे तो उन के साथ कैसे व्यवहार किया गया। वह मैं आपको बताना चाहता हूं। कम्पनी के लोग भारतीय दूतावास के अधिकारियों को लेकर वहां पहुंचे। पुलिस अधिकारी जोर देकर कह रहा था कि फैसला वहीं करा दिया जाय, मगर दूतावास के अधिकारी मामले को अपने हाथ में लेने की जिद करते रहे। उसके बाद मजदूरों को खाने पर भेज दिया गया। दूतावास के अधिकारियों ने बाद में मजदूरों से कहा कि उनके घर जा कर ही फैसला किया जाएगा...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must give a gist of it. Can't you read it in advance and give a list of it? What is it, you are reading like a student.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Since this is important, that is why I am reading it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I will not allow you to read. Please put the question now. If you want you hand it over to the Minister. That I will permit you.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Why do you take so much a rigid stand, Sir?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: All ight, Sir, I will put my question.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: At imes you are very liberal and at times ou are very rigid.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Yes, put our question now. No speech.

SHRI AJIT KUMAR MEHTA: Let me

omplete, Sir. यह रैलेवेंट प्वाइंट है । आप नहीं कहेंगे तो मैं बैठ जाउंगा यह मैं ग्रौथन्टिक रिपोर्ट ग्राप को बता रहा हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you don't ou questions, I will not allow you.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: I am gonig to put my questions, but let me make my point.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you, put your questions.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: I have promised that I will bring out some specific instances.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But you cannot take as much time as possible. I will not permit you. You have already taken more than twelve minutes.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Only five minutes more, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have told you that we have got to take up Private Members' Business and lunch also.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Sir, by that time I would have finished.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you prepared to put question or not. Otherwise I will call the next Member.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I don't want any discussion.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: I will put my question, but first I want to....

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: No discussion, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You would not listen to me. I am going to call the last speaker. Dr. Krupasindhu Bhoi, you put your questions.

प्रो० ग्रजित कुमार मेहता : : वहां जब दूतावास के ग्रधिकारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि बाद में वहां के कम्पनी वालों से मिलकर मजदूरों को ही कहा कि तुम जाकर काम करो नहीं तो तुम्हारे पासपोर्ट पर लिख दूंगा ग्रौर तुम कहीं के नहीं रहोगे । मैं कहना चाहता हुं कि पासपोर्ट भी पहले तो मजदूरों के हाथों में नहीं दिया गया, ग्रपने पास रख लिया गया । उसके बाद क्या होता कि जैसा ग्रापने कहा....

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you can't adjust according to the situation, you must excuse me, you are not a good Parliamentarian.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: I have told you I am going to bring out some specific points.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Put your questions within one or two minutes.

प्रो० ग्रजित कुमार मेहता : नो डिस्कशन मैं कह रहा था कि जैसा ग्रापने जवाब दिया है, कि जैसे ही ग्रापको पता चलता है, मामले पर कार्यवाही की जाती है । लेकिन ग्रापने इस मामले की जांच के लिये जिन को भेजा था, उसका जबाव ग्राया है कि जिस एजेंसी का नाम दिया गया है, वह एजेंट वहां से ग्रपने स्थान से बन्द करके चला गया है । वह एजेंसी मिल नहीं रही है । लेकिन ऐसा हुग्रा है कि उस एजेंट को लोगों ने पकड़कर थाने में पहुंचा दिया था । उसके बाद भोगेन्द्र झा जी को उस थाने के इंचार्ज से बात हुई । थाने के इंचार्ज ने भोगेन्द्र झा जी को जो जबाव दिया, वह मैं ग्रापको बताना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि.....

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: How can I answer?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He can't reply on anything and everything. What Bhogendra Jha has to do here?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Sir, let me complete.

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

श्री भोगेन्द्र झा को जबाव दिया थाने के इंचार्ज ने कि उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन दूसरे दिन वह छोड़ दिया गया। उससे ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकारी अधिकारियों की मिली-भगत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the Minister will reply.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: I have not completed. I have to put my question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you completed?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: I will put my question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want that the question should be put after lunch? Put the question now.

प्रो० अजित कुमार मेहता : विदेश विभाग के जिन अधिकारियों की एजेंटों मिली-भगत है, क्या सरकार की नजर में हैं, यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाई की गई है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

जो मजदूर विदेशों से वापस आना चाहते हैं, क्या सरकार उनको वापस लाने प्रबंध करेगी ?

जब इतने दिनों से यह क्रम चल रहा है, जिसके समाचार बराबर पत्रों में आ रहे हैं, तो ऐसी एजेंसियों का पता लगाने के प्रयास अब तक क्यों नहीं किये गये हैं, यदि किये गये हैं तो ऐसी एजेंसियां कितनी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है ?

जो एजेंट सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को ध्यान में रखकर कि बाहर भेजे जाने वाले प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमानत की रकम जमा करना एजेंट के लिये बाध्य कर दिया जाय, बाहर जाने वाले व्यक्तियों से ही यह पैसा अग्रिम लेना शुरू करें, उन को रोकने के लिये सरकार कौन सा प्रावधान करने जा रही है ?

जो मजदूर विदेशों में भेजे जा चुके हैं, उनको मानवोचित सुविधा दिलाने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

बेकारी से तंग आकर, मजदूर हो कर अमानवीय शर्तों पर विदेश जा कर अपनी जीविका अर्जित करने की भारतीय मजदूरों की प्रवृत्ति के प्रति रुचि पैदा करने के लिये देश में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सरकार कौन सा कारगर कदम उठा रही है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is over. Mr. Minister, you can reply now. This question will not end.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Sir, you did not allow me to complete it in peace.

MR. DEPUTY-SPEAKER: To-day is the last day. So many items have to be taken up.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I have explained earlier that this matter was being dealt with by the External Affairs Ministry. Now the Labour Ministry is in charge. Now it has come to my lap, and I have to answer.

After the transfer of work from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Labour in September 1981, 158 individual complaints alleging exploitation, cheating, breach of employment contract, under-payment of dues etc., were received in the Ministry of Labour. The Protector of Immigrants has been directed not to grant any immigration clearance to the firms involved in these cases. It has been difficult for the Government to bring such culprits to book as firstly, usually there is no evidence; and secondly, there is no legal provision to debar agents from charging arbitrary fees from the workers. In cases of substituting of contracts and poor

living/working conditions, necessary assistance is provided by the Indian Missions who first intervene with the employer to redress the grievance, and if that fails, provide necessary assistance to the workers to take up the matter with the local authorities.

The Indian Missions abroad have been specifically instructed to intervene in this matter. Wherever there has been a violation of the guarantee, or agreement that has been given while recruiting these people, by the various foreign agencies.

About the comprehensive Bill, the Minister has already given an assurance on the floor of the Rajya Sabha that a comprehensive Immigration Bill will be brought forward in the next Budget session. That is what he has said.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: I want a clarification. What about the Immigration Officers conniving with those people? You must have read this news item.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I have already said that if there are any specific instances, they may be brought to our notice. Let the hon. Member give them.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: You must have read the news item.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Instead of reading all those things, you must read the rules also—in addition to these things. Now Dr. Krupasindhu Bhoi.

DR. KRUPASIDHU BHOI (Sambalpur): This particular question has been discussed on the floor of the House many times, with reference to the Department of Labour, sometimes with reference to the Ministry of External Affairs and sometimes the Ministry of Home Affairs. In the last session also, I had asked a specific question from the Labour Ministry and he had promised to have a comprehensive legislation during 1982-83. India possesses the third largest skilled man power in the world; and unskilled labour in our country will be the largest compared to other countries, more than China and other populated countries. Internationally, our skilled workers have a good reputation because they are very hard working people. Many countries lack in skilled workers and they are coming over India and recruiting our skilled workers for their infrastructure, industries and other things.

The answer given by the Minister was not much elaborate. In the statement, he has stated. "In the latest case reported to the Police on the 10th October, 1982, 3 Travel Agents of Delhi were arrested." What follow up action the Department has taken should be known to us? What are the terms of reference for the comprehensive legislation? Whether Government will form their own exporting agency or corporation to export human resources outside the country. What is the number of travel agents legally registered in the country? Are they authorised agents or not? Whether the Government has given permits to individuals for export of human resources who are not technically competent or who have got no knowledge about the man power to be exported. I want to know the names of the people who have been given these export licences and under what circumstances they have been given these licences?

Instead of sending skilled workers, these racketeers send unskilled workers; and many MPs are also victims to this thing because they have to sign the passports. Our foreign missions repatriate them to our country because they are unskilled workers and are not fit to work under those projects. Prof. Ajit Kumar Mehta had put a pertinent question to the Minister. A few days back in Delhi all the papers carried a news of harassment of Urea labourers. Delhi University students had brought it to the notice of the Government also. M/s. Jayaprakash and Associates, a construction company has some agents in Orissa. Two or three years back, they were papers; now they are multi millionaires will the Department of Home Affairs investigate who are those agents, what were their assets then and what are their

[Dr. Krupasindhu Bhoi]

assets now and how they have accumulated this money? Previously, these labourers were given an impression that they would get a salary of Rs. 3000 in Iran and Iraq and other countries. But now it is found that the people who had been sent there are sending only Rs. 800 to their families and the other money is being taken by Jayaprakash and Associates and other people. Then Mr. Mehta told that there is a complaint that all the people who were sent to Iraq, their fate is in a very bad condition. I want to know what is the present condition of that particular contingent in Iran and Iraq? Whether the Ministry has got any information. More than 300 labourers had paid money through the agent of Jayaprakash and Associates, who has re-recently built a three-star hotel in Banpur, Orissa. That fellow has not yet returned the money which these poor labourers had paid—it was more than Rs. 3-4000 per head.

And they are now in Delhi going from pillar to post. In so many hotels they are getting only Rs. 5/- per day and we do not know whether the Government has got any information. If they have not got any information. I can supply the information. I want to know whether the Home Minister will investigate and they will make proper arrangements to send those labourers to Orissa with their wages which they have earned.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: About this particular company, M/s. Jayaprakash Construction Company, the facts that have been mentioned by the hon. Member are presently not with me. Whatever information he can give, I will be very much thankful to the hon. Member for giving me the information. We will certainly take action. If they have contravened any law or Act, certainly, deterrent punishment will be given to them. We have already given instruction—I have already read it out—that if any of these companies or individuals have contravened the law or regulations they can be black listed and they should not be given any permission to do so.

Again, about this comprehensive Bill, I have already mentioned that the Labour Minister has stated in the Rajya Sabha that he will be bringing forward a Bill during the Budget Session of Parliament.

The hon. Member has spoken about skilled labour and unskilled labour. We have got a very impressive record of sending our people abroad. In Bahrain—I am giving approximate figures of Indian workers employed in foreign countries—there are 30,000; in Iraq there are 27,000; in Jordan, there are 4,000 to 5,000; in Kuwait there are 1,25,000; in Libya there are 40,000; in Oman there are 65,000; in Qutar there are 30,000 in Saudi Arabia there are 1,20,000 to 1,50,000; in United Arab Emirates there are 2,50,000; in Yeman Arab Republic there are 7,000; and in Yeman People's Democratic Republic there are 1,000.

I have already stated, the steps that are being taken by our Embassies abroad, to watch these people and whatever assistance this is necessary is being provided to them.

I may also tell you in this connection that a pamphlet has been published by the Labour Ministry. The pamphlet gives details of living conditions, working conditions and wage expectations etc. This pamphlet has been prepared for the guidance of the propective emigrants and emigrants abroad. These pamphlets have been circulated to the State Governments for translation into regional languages and for arranging wide publicity. Copies of the pamphlets have also been sent to the distribution branch of the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat for distribution among Members of Parliament. All India Radio and Doordarshan have also been requested to publicise a set of do's don'ts for the information of the prospective emigrants. The Films Division have also been requested to produce a small documentary film for general viewing.

We have been taking all precautionary measures so that these innocent people in their anxiety to go abroad may not be exploited by unscrupulous elements. So, whatever is possible is being done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Satyanarayan Jatiya.

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, 10 अक्तूबर को 'वीसा रेकेट' का यह समाचार समाचार पत्रों में आया था जिसकी वजह से हम इस महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह दो नम्बर का धंधा करने वाले बड़ी मात्रा में दिल्ली में ही नहीं है अपितु, सारे देश में है। इनके माध्यम से जो देश में बेरोजगार लोग हैं, उन बेरोजगार लोगों को लालच दे कर और यह बता कर कि विदेशों में यदि तुम रोजगार के लिये जाओगे तो तुम्हें इतनी सुविधायें मिलेंगी, इतना पैसा मिलेगा और आराम भी मिलेगा। इस लुभावने आकर्षण के कारण, बेरोजगारी की स्थिति के कारण, वह आदमी विदेश में चला जाता है। यह बात नहीं है कि बिना पढ़े लिखे लोग जाते हैं पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। डाक्टर्स और इंजीनियर्स भी जाते हैं।

म आपको इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे एक मित्र इस योजना के अन्तर्गत विदेश में गये। वहां की स्थिति इतनी शर्मनाक है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता हू। वहां किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलता है। यह एक दास्तान है, जिसको मैं मंत्री जी को अलग से बताऊंगा, लेकिन आज जो इस तरह के 'रैकेट्स' हैं, उसमे स्थिति बहुत खराब है।

आपने बताया है कि 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 37 मामलों में जांच पड़ताल चल रही है। इस तरह के जो लोग जनता को फंसाने का काम करते हैं, इनके नाम अखबारों में प्रकाशित किये जाने चाहियें ताकि अन्य लोग इनके चंगुल में न फंसे।

हमारे यहां से कुछ मजदूर आये थे उनसे हजारों रुपया 'एडवांस' के रूप में ले लिया गया। मैंने उनकी मदद करनी चाही, लेकिन उन लोगों ने वह पैसा वापिस नहीं किया। गरीब लोग अपने घर का जेवर बेच कर पैसा लाते हैं और उस पैसे को ये लोग ले लेते हैं। यह गुडों का एक बड़ा रैकेट होता है जो मेहनतकश लोगों का शोषण करता है। ये लोग हमारे देश के लिए कलंक हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। मेरी मांग है कि इस तरह के जो लोग पकड़ में नहीं आते हैं, उनको पकड़ने के लिये सरकार विशेष व्यवस्था करे और जो लोग पकड़े जाते हैं उनके नाम प्रकाशित किये जायें, ताकि अन्य लोग उनके चंगुल में न आ सकें।

हमारे यहां इतनी बेरोजगारी है। दो करोड़ से ज्यादा खेतीहर मजदूर हैं और लाखों शिक्षित बेरोजगार हैं। रोजगार के लिये हर आदमी परेशान रहता है। इस लिये सरकार की ओर से किसी प्रभावी एजेंसी का इंतजाम होना चाहिये जो विदेश में रोजगार पाने वालों को सही मार्गदर्शन दे सके और जो लोग विदेश चले जाते हैं, उनके साथ ठीक व्यवहार हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिये भी सरकार व्यवस्था करे। इस बारे में सरकार क्या करने जा रही है उसके बारे में जानकारी दी जाए।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: The hon. Member has suggested that the names of these people, who are convicted, should be published in the newspapers. We will examine it. If it is feasible under the relevant rules and regulations...

MR. DEPUTY-SPEAKER: So that he may not commit crime again.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Certainly his suggestion will be taken into consideration.

[Shri P. Venkatasubbaiah]

I have already said that several State Governments have set up manpower corporations to regulate, mobilise and rationalise the thing. That is why, we thought that at the central level, we need not have anohter manpower corporation. We want to see that the monitoring and coordination is done in such a manner that the people are not exploited by unscrupulous elements. I assure the hon. Member on that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House now adjourns for lunch and will meet again at 2.20.

13.20 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till twenty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty-five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR ADEQUATE TRAIN SERVICES FOR THE NORTHERN PART OF KERALA.

SHRI V. S. VIJAYARAGHAVAN (Palghat): Under Rule 377 I make the following statement:

Rail facilities are quite inadequate in the northern parts of Kerala. Thousands of people from these areas are travelling to Bombay, Delhi and other Major cities every day. In the absence of any direct train, these passengers are facing a lot of difficulties. Inspite of repeated representations for improved rail facilities, Malabar continues to be neglected.

Recently, the Railway Board took a decision to attach 7 through coaches to Delhi and 2 to Bombay to the newly introduced Mangalore-Palghat link Express from 1-10-1982. This was widely welcomed by the public. But, strangely, the Board concelled its decisions at the last minute. This has caused a considerable amount of resentment among the people of North Kerala, who have a long standing grievance that they are being neglected by the Railways. Through coaches to Delhi and Bombay would have provided some relief to the people of this areas. Therefore, I would request the hon'ble Minister for Railways to take the following steps to solve the problems of the travelling public in North Kerala:—

(1) Introduce through coaches to Delhi and Bombay as was decided earlier by the Railway Board.

(2) Extend the newly introduced Mangalore-Palghat Link Express to Coimbatore.

(3) Construct a platform at Shoranur junction on the link line.

(ii) MEASURES TO CONTROL LEPROSY

SHRI RASABEHARI BEHERA (Kalahandi): Under Rule 377 I make the following statement:

The dreaded disease of leprosy is spreading with a menacing speed in Orissa. It has particularly struck a large number of tribal villages as well as coastal areas. According to an estimate, 15 lepers for every 1000 population are residing in Orissa. The number of such lepers is increasing further in Bolangir, Sambalpur, Kalahandi and some coastal districts also.

One of the major reasons for the widespread disease is the graphide content of water from springs which is sole source of drinking water in the hilly areas. A large number of lepers die every year and new lepers come in their place in Puri district.

Unless immediate measures are taken to control the leprosy the situation may be further aggravated. Therefore, Government of India should pay special attention to check spreading of this dangerous disease. Anti-leprosy programme should be implemented more vigorously. State Government, Central Government and voluntary organisations should take keen interest to control the disease. Leprosy rehabilitation colonies should be set up without delay. Adequate measures should be taken to provide proper treatment to the lepers.